ALFAAZ TIMES

हर खबर, हर शहर

DIGITAL E-PAPER

PRGI APPLICATION UNDER PROCESS
Application No. MAHMUL/2023/88574

GST GSTIN

UDYAM REGISTERED

DIGITAL NEWS NETWORK
भारत का भरोसेमंद बहुभाषी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क
11+ Languages | 24×7 Live | e-Paper Daily

हमारा App डाउनलोड करें
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

www.alfaaztime.digital
info@alfaaztime.digital
+91
FOLLOW US:

तेज़ | सटीक | निष्पक्ष | जनहित में | सच की आवाज़ | जन-जन की आवाज़ | निडर पत्रकारिता

रक्षा

बिजापुर में माओवादियों के छुपाए 711 BGL शेल सुरक्षा बलों ने बरामद किए



छत्तीसगढ़ में कार्यरत सुरक्षा बलों ने उग्रवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक बड़े मात्रा में हथियारों को जब्त किया है। बिजापुर जिले में एक लक्षित अभियान के दौरान प्रशासन ने माओवादी समूहों द्वारा छुपाए गए 711 BGL शेल बरामद किए। इतनी बड़ी संख्या में शेल की बरामदगी इस बात की पुष्टि करती है कि राज्य के सुरक्षा विभाग बाएं पंथी उग्रवादियों (LWE) के लॉजिस्टिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिजापुर क्षेत्र में सक्रिय माओवादी कमांडरों की उपस्थिति के कारण यह क्षेत्र कंटर-इंसर्जेन्सी ऑपरेशन्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।

भंडार की सटीक स्थिति और ऑपरेशन के समयरेखा से जुड़ी विस्तृत जानकारी अधिकारियों द्वारा समीक्षाधीन है, हालांकि यह जब्त अस्त्र-शस्त्र उग्रवादियों की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने की उम्मीद जताती है। बरामद किए गए हथियारों को आगे की जांच और निपटान के लिए संबंधित सैन्य और पुलिस इकाइयों को सौंप दिया गया है।

यह विकास छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की निरंतर सतर्कता को दर्शाता है। राज्य प्रशासन ने नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र समूहों द्वारा उत्पन्न खतरों को निष्क्रिय करने को प्राथमिकता दी है।

देश

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट: फतवों का कोई कानूनी दर्जा या बाध्यकारी प्रभाव नहीं



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने धार्मिक निर्देशों के कानूनी दर्जे पर एक स्पष्ट निर्णय दिया है, जिसमें कहा गया है कि फतवों के पास न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कोई कानूनी स्थिति या बाध्यकारी प्रवर्तनीयता नहीं है।

बेंच ने इस स्थिति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिससे यह सिद्धांत दोहराया गया कि भारत में धार्मिक निर्देशों का कानूनी दस्तावेजों के समान कोई वजन नहीं होता।

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि हालांकि व्यक्ति धार्मिक मार्गदर्शन का पालन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे निर्देशों को राज्य द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता और न ही इनका उपयोग नागरिक या आपराधिक प्रक्रियाओं में कानूनी दावों के आधार के रूप में किया जा सकता है।

यह निर्णय भारतीय कानूनी ढांचे के धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को रेखांकित करता है, जहाँ कानून और व्यवस्था के मामलों में न्यायिक प्राधिकरण धार्मिक घोषणाओं से अधिकतर होता है।

धर्म

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण मिशनरी और चर्चों की हटाई की मांग



छत्तीसगढ़ के एक गाँव के निवासियों ने अपने समुदाय में मिशनरियों और चर्चों की उपस्थिति के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने इन धार्मिक संस्थानों के अपने पारंपरिक जीवन के तरीके पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए उनकी हटाई की मांग की है। ग्रामीणों की मांग ने भारत के ग्रामीण इलाकों में धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म-आधारित संगठनों की भूमिका के बारे में एक बहस छिड़ दी है। स्थानीय अधिकारी वर्तमान में स्थिति का आकलन कर रहे हैं और ग्रामीणों की चिंताओं का समाधान करने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य

बिलासपुर सिम्स का बड़ा कारनामा: शरीर में घुसे 4 फीट लंबे सरिये को निकालकर बचाई जान



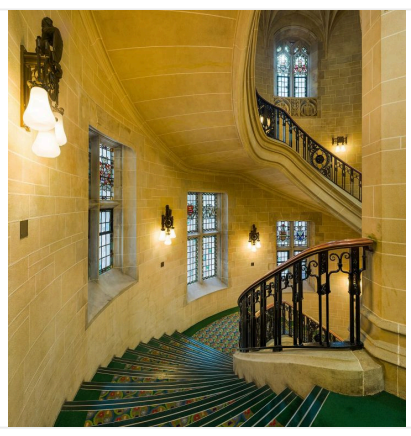
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल में एक चौंकाने वाला चिकित्सीय कारनामा हुआ, जहाँ डॉक्टरों की टीम ने एक गंभीर रूप से घायल निर्माण श्रमिक की जान बचा ली।

घटना तब हुई जब एक मिस्त्री, जो भवन की दूसरी मंजिल पर काम कर रहा था, नीचे गिर गया। गिरते समय उसके शरीर में करीब चार फीट लंबा सरिया आर-पार घुस गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

घायल मिस्त्री को गंभीर हालत में सिम्स अस्पताल रेफर किया गया। वहाँ डॉक्टरों की टीम ने तुरंत जटिल सर्जरी शुरू की और सावधानी के साथ उसके शरीर से घुसा हुआ सरिया बाहर निकाला। ऑपरेशन सफल रहा और मरीज की जान बच गई है। वह अब डॉक्टरों की निगरानी में है। यह घटना निर्माण स्थलों पर सुरक्षा उपायों की अहमियत और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के महत्व को रेखांकित करती है।

देश

सुप्रीम कोर्ट: अनिवार्य रिटायरमेंट आदेश दंडात्मक नहीं, प्रशासनिक हैं



भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य रिटायरमेंट आदेशों के कानूनी स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। शीर्ष अदालत ने निर्णय दिया कि ऐसे आदेश न तो दंडात्मक (punitive) हैं और न ही अपमानजनक (stigmatic)। यह फैसला इस बात पर बहस को समाप्त करने के लिए है कि शीघ्र रिटायरमेंट से कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है।

कोर्ट ने जोर दिया कि अनिवार्य रिटायरमेंट सरकार या नियोक्ता द्वारा वर्कफोर्स प्रबंधन के लिए लिया गया एक प्रशासनिक निर्णय है। यह किसी गलतव्यवहार के लिए कर्मचारी को सजा देने का कोई अनुशासनात्मक कदम नहीं है। इसलिए, यह व्यक्ति की ईमानदारी या पेशेवर प्रतिष्ठा पर नकारात्मक रूप से प्रकाश नहीं डालता।

यह फैसला उन नागरिक सेवा अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पष्टता प्रदान करता है जिनकी शीघ्र रिटायरमेंट होती है। इन आदेशों को गैर-दंडात्मक घोषित करके, कोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे प्रशासनिक कदमों में अनुशासनात्मक बर्खास्तगी या निलंबन जैसा कोई कानूनी वजन या सामाजिक अपमान नहीं होता।

यह निर्णय अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं और मानव संसाधन के प्रशासनिक प्रबंधन के बीच के अंतर को रेखांकित करता है। यह भारत में सेवा संबंधी मामलों और रिटायरमेंट नीतियों से जुड़े भविष्य के मामलों के लिए एक मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में काम आएगा।

राजनीति

छत्तीसगढ़ CM साई ने बास्तर में राष्ट्रपति मुर्मु का स्वागत किया, कांग्रेस पर निशाना



छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने बास्तर क्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का स्वागत किया। इस भेंटवार्ता को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहाँ राज्य सरकार ने आदिवासी बहुल क्षेत्र में राष्ट्रपति से संवाद किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साई ने क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अब तक आदिवासी समुदाय को केवल 'वोट बैंक' के रूप में उपयोग किया है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य चयनात्मक लाभ था, न कि आदिवासियों का समग्र विकास।

इन बयानों से छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनजातियों के प्रतिनिधित्व और कल्याण के इर्द-गिर्द चल रही राजनीतिक चर्चा को नई गति मिली है। राष्ट्रपति की बास्तर यात्रा को स्थानीय जनता और जनजातीय नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण जुड़ाव के रूप में देखा जा रहा है।

मनोरंजन

अभिजीत भट्टाचार्य की टिप्पणी पर डालर मेहंदी के पुत्र गुरदीप ने जवाब दिया



अभिनेता अभिजीत भट्टाचार्य द्वारा गायक डालर मेहंदी पर की गई टिप्पणी के बाद मनोरंजन जगत में एक छोटा सा विवाद खड़ा हो गया है। अभिजीत की यह टिप्पणी, जिसे डालर मेहंदी पर एक निशाना साधा जाना माना गया, के बाद डालर के पुत्र गुरदीप मेहंदी ने जवाब दिया है।

गुरदीप मेहंदी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हालांकि कलात्मक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन कुछ कलाकार संदर्भ या संवेदनशीलता के बिना बेफिक्र बातें करते हैं। उनकी यह प्रतिक्रिया उनके पिता की प्रतिष्ठा की रक्षा करने की दिशा में कदम माना जा सकता है।

यह घटना सार्वजनिक हस्तियों और उनके सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर आपसी बातचीत के चारों ओर चल रही चर्चा को उजागर करती है। चूंकि दोनों भारतीय मनोरंजन क्षेत्र के प्रमुख हस्तियां हैं, इसलिए उनके बीच यह शब्दयुद्ध प्रशंसकों और मीडिया दोनों के लिए रोचक है।

इस समय तक, किसी भी पक्ष से कोई आधिकारिक या कानूनी कार्रवाई की खबर नहीं मिली है, और यह मामला अभी भी उद्योग के भीतर शब्दों के आदान-प्रदान तक सीमित है।

नौकरी

छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड 2026: 1,501 AE, JE और अन्य पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू



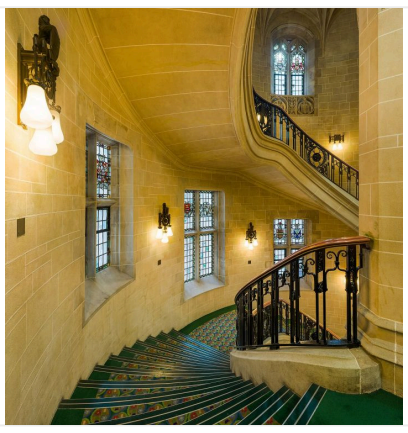
छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी लिमिटेड (CGSPCL) ने वर्ष 2026 के लिए अपने भर्ती अभियान की शुरुआत कर दी है। यूटिलिटी बोर्ड ने विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी भूमिकाओं के लिए कुल 1,501 रिक्तियों की घोषणा की है।

भर्ती प्रक्रिया में सहायक इंजीनियर (AE), जूनियर इंजीनियर (JE) और अन्य स्टाफ श्रेणियों के पद शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

इस कदम से छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों से उम्मीदवारों की बड़ी संख्या को आकर्षित करने की उम्मीद है, क्योंकि बिजली क्षेत्र क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रोजगारदाता बना हुआ है। उम्मीदवारों को विशिष्ट पात्रता मानदंडों और आवेदन अंतिम तिथियों के लिए आधिकारिक अधिसूचना की जांच करने की सलाह दी जाती है।

देश

सुप्रीम कोर्ट: अनिवार्य रिटायरमेंट कर्मचारी की गलती नहीं



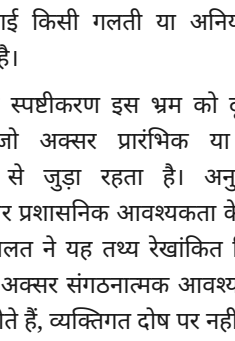
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी और निजी सेवा संबंधी मामलों में अनिवार्य रिटायरमेंट की प्रकृति के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने निर्णय लिया है कि नियमित उम्र सीमा से पहले रिटायर होना अपने आप में कर्मचारी द्वारा की गई किसी गलती या अनियमितता का संकेत नहीं है।

यह कानूनी स्पष्टीकरण इस भ्रम को दूर करने के लिए है जो अक्सर प्रारंभिक या जबरदस्ती रिटायरमेंट से जुड़ा रहता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई और प्रशासनिक आवश्यकता के बीच अंतर करके, अदालत ने यह तथ्य रेखांकित किया है कि ऐसे निर्णय अक्सर संगठनात्मक आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं, व्यक्तिगत दोष पर नहीं।

यह फैसला भविष्य के सेवा विवादों के मामलों के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे कर्मचारी जो अनिवार्य रिटायरमेंट से गुजरते हैं, उन्हें केवल सेवा से अपने निकास के तरीके के कारण उनके पेशेवर रिकॉर्ड में अमानवीय रूप से दंडित या नकारात्मक रूप से नहीं देखा जाता है।

देश

छत्तीसगढ़ के अबुझमाद में रेलवे ट्रैक ने अलगाव तोड़ा



छत्तीसगढ़ का दूरदराज इलाका अबुझमाद, जो लंबे समय से अपनी अलगाव और सुरक्षा चुनौतियों के लिए जाना जाता रहा है, अब बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव देख रहा है। इस क्षेत्र में रेलवे ट्रैक अब फैल चुके हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो रहा है।

इस विकास को जिले के लिए प्रगति का रास्ता माना जा रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से व्यापक आर्थिक नेटवर्क से कटकर रह गया था। रेलवे लाइन की उपस्थिति से गतिशीलता बढ़ने और माल-सामान तथा लोगों के आवागमन में सुधार होने की उम्मीद है।

ऐसे क्षेत्र के लिए, जो दशकों तक अलग-थलग रहा है, यह बुनियादी ढांचे में सुधार राज्य और देश के बाकी हिस्सों से एकीकरण की ओर एक ملمूला कदम है। ध्यान स्थानीय समुदाय के लिए टिकाऊ विकास में इस कनेक्टिविटी के रूप में बदलने पर केंद्रित है।

खेल

भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर है कन्वे, ब्लैक कैप्स तलाश रहे प्रतिस्थापन



न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेवोन कन्वे को एक अज्ञात चोट के कारण भारत के खिलाफ आगामी ODI सीरीज से बाहर कर दिया गया है। यह ब्लैक कैप्स के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है, क्योंकि कन्वे उनकी हालिया सफलताओं में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड अब कन्वे की जगह के लिए एक उपयुक्त प्रतिस्थापन खोजने में सक्रिय रूप से जुटा है। यह श्रृंखला [दिनांक डालें] से शुरू होगी और कई भारतीय शहरों में खेली जाएगी।

अपराध

छत्तीसगढ़ के करगूटा पहाड़ों के पास माओवादियों का विस्फोटक भंडार



छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने माओवादी उग्रवादियों के पास एक बड़ा विस्फोटक भंडार बरामद किया है। यह खोज राज्य में माओवादियों के एक प्रमुख ठिकाने के रूप में जाने जाने वाले करगूटा पहाड़ों के पास हुई। बरामद किए गए 711 विस्फोटक गोले क्षेत्र में सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा हैं। अधिकारी वर्तमान में विस्फोटकों के उद्देश्य और उपयोग का पता लगाने में जुटे हैं।

नौकरी

दीवाली से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने 1,703 सरकारी नौकरियों की घोषणा की



छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 1,703 नई सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। दीवाली त्योहार से ठीक पहले इस महत्वपूर्ण भर्ती अभियान की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य स्थानीय कार्यबल को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

यह घोषणा राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए की गई है। सरकार ने प्रमुख त्योहार से पहले इन पदों की घोषणा करके नौकरी चाहने वालों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने और त्योहार के दौरान मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया है।

हालांकि विभिन्न विभागों में इन पदों का वितरण और विस्तृत पात्रता मानदंड भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन राज्य अधिकारियों ने 1,703 खाली पदों की कुल संख्या की पुष्टि कर दी है। यह कदम छत्तीसगढ़ भर से योग्य उम्मीदवारों से एक बड़ी संख्या में आवेदन आने की उम्मीद जताता है।

सरकार का दीवाली से पहले इन नौकरियों की घोषणा करने का निर्णय राज्य में बेरोजगारी को दूर करने और सार्वजनिक सेवा क्षमता को बढ़ाने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्थानीय

छत्तीसगढ़ न्यूज़ राउंडअप: आज की प्रमुख खबरों का सारांश



NPG News ने छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के लिए 'CG Top News Today Live' शीर्षक से एक डिजिटल सारांश प्रकाशित किया है। यह प्रकाशन पाठकों को दिनभर की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का एक केंद्रीकृत दृश्य प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें एक क्लिक में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।

यह न्यूज़ राउंडअप राज्य भर की विभिन्न रिपोर्टों को एकत्रित करता है, जो स्थानीय दर्शकों के लिए प्रासंगिक विषयों को कवर करता है। इन कहानियों को एक ही स्थान पर संकलित करके, मंच छत्तीसगढ़ की वर्तमान घटनाओं में रुचि रखने वाले निवासियों और हितधारकों के लिए जानकारी उपभोग को सरल बनाना चाहता है।

यह पहल भारतीय डिजिटल मीडिया में एक व्यापक रुझान को दर्शाती है, जहाँ क्षेत्रीय समाचार आउटलेट स्थानीय दर्शकों को दैनिक विकासों के बारे में सूचित रखने के लिए कुशल और आसानी से नेविगेट करने योग्य सारांश बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

अपराध

महादेव ऐप सह-संस्थापक रवि उप्पल को दुबई में हवाला के आरोप में हिरासत में लिया गया



महादेव बेटिंग ऐप के सह-संस्थापक रवि उप्पल को दुबई में हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई हवाला लेन-देन से जुड़े गंभीर आरोपों के बाद की गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी को करोड़ों रुपये के हवाला ट्रांजैक्शन में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। यह मामला ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्मों से जुड़े नियामक और कानूनी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

यह घटना डिजिटल गेमिंग ऐप्स से जुड़े वित्तीय अपराधों की सीमा पार प्रकृति को उजागर करती है। दुबई की प्रशासनिक एजेंसियों ने अवैध फंड ट्रांसफर के आरोपों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, ध्यान कथित हवाला नेटवर्क की सीमा और ऐप के नेतृत्व द्वारा इन वित्तीय गतिविधियों में निभाई गई भूमिका पर केंद्रित रहेगा।

राजनीति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपाहिज देखभाल केंद्रों में मौतें और चिकित्सा लापरवाही पर उठाई चिंता



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के अपाहिज देखभाल केंद्रों में प्रदान की जा रही चिकित्सा सेवाओं और प्रबंधन को लेकर गंभीर चिंता जताई है। न्यायालय ने इन संस्थानों में बनी स्थिति को 'दुर्भाग्यपूर्ण' (sorry state of affairs) बताते हुए कमजोर वर्ग के कल्याण में हो रहे व्यवस्थागत विफलताओं पर प्रकाश डाला है।

न्यायालय ने निवासियों की मौतों के मामलों और चिकित्सा उपचार प्रोटोकॉल में लापरवाही की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ये निष्कर्ष संकेत देते हैं कि ऐसे संस्थानों में अपेक्षित देखभाल के मानक और वास्तविक स्थिति के बीच एक बड़ा अंतर है, जिससे प्रशासन के इन मामलों को संभालने के तरीके पर न्यायिक निरीक्षण की आवश्यकता पड़ी है।

हालांकि तत्काल रिपोर्ट में व्यक्तियों के नाम या घटनाओं की सटीक संख्या का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन न्यायालय की यह हस्तक्षेप सरकार की सुविधाओं में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्टाफ की जवाबदेही के संबंध में जांच की अत्यावश्यकता को रेखांकित करता है।

यह आदेश राज्य प्रशासन के लिए एक निर्देश है कि वे इन कमीओं को तुरंत दूर करें और कानूनी मानकों के अनुरूप अपाहिजों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा सुनिश्चित करें।